विचार बिन्दु

निरन्तर बदलने की इच्छा रखना एक ताकत होती है, चाहे इसकी वजह से कंपनी का एक बड़ा हिस्सा कुछ देर के लिए पूरी तरह से अव्यवस्थित क्यों ना हो जाए। –जैक वेल्व

जल के बिना जीवन असंभव है, जल संरक्षण केवल विकल्प नहीं, बल्कि आवश्यकता है

जल जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। यह केवल एक प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के अस्तित्व का आधार है। मानव सभ्यता का इतिहास गवाह है कि जहां पानी है, वहीं समृद्धि है। किंतु विडंबना यह है कि जिस संसाधन के बिना जीवन असंभव है, उसी का सबसे अधिक दुरुपयोग हम कर रहे हैं। विश्व स्तर पर जल संकट एक गंभीर चुनौती बन चुका है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2050 तक विश्व की आधी से अधिक आबादी जल संकट का सामना कर सकती है। भारत जैसे कृषि प्रधान और जनसंख्या बहुल देश के लिए यह स्थिति और भी भयावह हो सकती है। बढ़ती जनसंख्या, अनियंत्रित औद्योगिकीकरण, शहरीकरण की तेज़ रफ्तार और जल संसाधनों का अंधाधुंध दोहन इस संकट को गहरा कर रहा है। भारत में औसतन प्रतिवर्ष 1170 मिलीमीटर वर्षा होती है, परंतु वर्षा का वितरण असमान है। राजस्थान जैसे राज्य, जो शुष्क और अर्ध–शुष्क क्षेत्र में आते हैं, वहां यह स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण है।

भारतीय संस्कृति में जल को देवता का स्थान दिया गया है। हमारे ग्रंथों में जल को अमृत, जीवन और शक्ति का प्रतीक माना गया है। प्राचीन भारत में जल संचयन और संरक्षण के अनेक अनूठे तरीके विकसित किए गए। गांव–गांव में तालाब, कुएं, बावड़ियां और जोहड़ जैसी संरचनाएं केवल जल का स्त्रोत नहीं, बल्कि सामाजिक जीवन का केंद्र हुआ करती थीं। यह व्यवस्थाएं हमें बताती हैं कि हमारे पूर्वजों ने कितनी दूरदर्शिता के साथ प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया। दुर्भाग्यवश, आधुनिक विकास की दौड़ में इन परंपराओं की उपेक्षा हुई। नदियों के किनारे कचरा डालना, तालाबों पर अतिक्रमण, वर्षा जल को व्यर्थ बहने देना और कंक्रीट के जंगल खड़े करना–इन सबने जल संकट को बढ़ावा दिया।

यदि भारत में जल संकट की गंभीरता को समझना है, तो राजस्थान का उदाहरण सबसे उपयुक्त है। यह राज्य भौगोलिक दृष्टि से मरुस्थलीय क्षेत्र है, जहां औसत वार्षिक वर्षा मात्र 100 से 500 मिलीमीटर के बीच होती है। इसके बावजूद राजस्थान के लोगों ने जल संरक्षण के अद्भुत और टिकाऊ उपाय अपनाए। बावड़ी, जोहड़, टांका, नाड़ी जैसी पारंपरिक संरचनाएं केवल जल भंडारण के साधन नहीं, बल्कि जीवनरेखा थीं। बावड़ियां सीढ़ीनुमा कुएं होते थे, जिनमें वर्षा का पानी इकट्ठा किया जाता। इनका उपयोग पीने के पानी के साथ–साथ गर्मियों में ठंडक के लिए भी होता था। जोहड़ गांवों में बनाए गए छोटे जलाशय होते थे, जो वर्षा जल को रोककर भूजल स्तर को बनाए रखते थे। टांके और नाड़ियां मरुस्थल क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन के ये प्रमुख स्त्रोत थे, जो पशु और मानव दोनों के लिए उपयोगी रहे। सदियों तक इन पारंपरिक प्रणालियों ने राजस्थान को जल संकट से बचाए रखा। किंतु आधुनिकता के दबाव, जनसंख्या वृद्धि और अंधाधुंध भूजल दोहन ने स्थिति को बदतर बना दिया। भूजल स्तर कई क्षेत्रों में 400 फीट से भी नीचे चला गया।

छोटे-छोटे कदम बड़े बदलाव ला सकते हैं। नलों को खुला न छोड़ना, स्नान, कपड़े और वाहन धोने में अनावश्यक पानी खर्च न करना, रीसायकल और री-यूज को जीवनशैली का हिस्सा बनाना-ये आदतें हमें आज ही अपनानी होंगी। विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि यदि समय रहते जल संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया गया, तो भविष्य में पानी को लेकर संघर्ष और युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

जब जल संकट चरम पर था, तब राजस्थान ने फिर से अपनी जड़ों की ओर लौटने का प्रयास किया। इसका सबसे प्रेरक उदाहरण है अलवर जिले का तरुण भारत संघ और अरवरी नदी का पुनर्जीवन। 1985 में राजेंद्र सिंह, जिन्हें आज जलपुरुष कहा जाता है, ने जोहड़ों के पुनर्निर्माण का अभियान शुरू किया। सामूहिक प्रयास से सैकड़ों जोहड़ पुनर्जीवित हुए और परिणामस्वरूप अरवरी नदी, जो वर्षों से सूखी थी, फिर से बहने लगी। आज यह नदी लगभग 90 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है। इस प्रयास से 1000 से अधिक गांवों में भूजल स्तर बढ़ा, कृषि उत्पादन सुधरा और पलायन रुका। यह उदाहरण बताता है कि सामूहिक प्रयास और पारंपरिक तकनीकों का मेल असंभव को संभव कर सकता है।

राजस्थान सरकार ने जल संरक्षण की दिशा में कई महत्वपूर्ण पहलें की हैं। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान इस दिशा में एक उल्लेखनीय प्रयास है। इस योजना के तहत लाखों जल संरचनाएं बनाई या पुनर्जीवित की गईं। इससे भूजल स्तर में सुधार हुआ और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट कम हुआ। अटल भूजल योजना और जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण घरों तक पाइपलाइन से पानी उपलब्ध कराने और भूजल पुनर्भरण पर जोर दिया जा रहा है। 2003 में राजस्थान हाईकोर्ट ने भवन निर्माण में वर्षा जल संचयन को अनिवार्य किया था, लेकिन इसका पालन अपेक्षित स्तर तक नहीं हो सका। अब समय आ गया है कि इसे कठोरता से लागू किया जाए। कृषि क्षेत्र में बदलाव अनिवार्य है। भारत में कुल जल उपयोग का लगभग 80 प्रतिशत कृषि में होता है।

औद्योगिक और शहरी क्षेत्रों की चुनौतियां भी कम नहीं हैं। राजस्थान के औद्योगिक शहर जैसे भीलवाड़ा, पाली और सिरोही में वस्त्र उद्योग भारी मात्रा में पानी उपयोग करता है। कई इकाइयां अपशिष्ट जल बिना शुद्ध किए नदियों में छोड़ती हैं, जिससे जल स्त्रोत प्रदूषित हो रहे हैं। इन उद्योगों को एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाना अनिवार्य करना होगा और जल पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना होगा। शहरी क्षेत्रों में तेजी से बढ़ते कंक्रीट के जंगल ने वर्षा जल के रिसाव को लगभग समाप्त कर दिया है। इस स्थिति में परकोलेशन पिट्स, चेक डैम्स और कृत्रिम रिचार्ज संरचनाएं विकसित करनी होंगी। स्मार्ट सिटी योजनाओं में जल संरक्षण को प्राथमिकता देना आवश्यक है।

सरकारी प्रयास तभी सफल होंगे जब समाज की सक्रिय भागीदारी होगी। जल संरक्षण केवल योजनाओं या अभियानों का विषय नहीं, बल्कि हर नागरिक का दायित्व है। घर–घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करना अनिवार्य होना चाहिए। स्कूलों और कॉलेजों में जल संरक्षण शिक्षा को शामिल करना चाहिए। मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से जनजागरण अभियान चलाने होंगे। हर गांव, मोहल्ले और अपार्टमेंट में जल समितियां बनानी होंगी।

छोटे–छोटे कदम बड़े बदलाव ला सकते हैं। नलों को खुला न छोड़ना, स्नान, कपड़े और वाहन धोने में अनावश्यक पानी खर्च न करना, रीसायकल और री–यूज को जीवनशैली का हिस्सा बनाना–ये आदतें हमें आज ही अपनानी होंगी।

विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि यदि समय रहते जल संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया गया, तो भविष्य में पानी को लेकर संघर्ष और युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए अब यह समय केवल चिंतन का नहीं, बल्कि संकल्प का है। राजस्थान का अनुभव बताता है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी यदि संकल्प और सामूहिक प्रयास हों, तो सूखा इलाका भी पानी से लहलहा सकता है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि जल है तो कल है। यह नारा नहीं, बल्कि जीवन का सत्य है। यदि आज हम पानी को नहीं बचाएंगे, तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। अब समय है कि हम राजस्थान की प्रेरणा को पूरे देश में फैलाएं और हर बूंद की रक्षा का संकल्प लें। यही हमारी धरती, समाज और आने वाली पीढ़ियों के प्रति सच्ची जिम्मेदारी है।

–अतिथि संपादक,
अविनाश जोशी
वरिष्ठ पत्रकार एवं कॉरपोरेट सलाहकार

रोशनी लौटाने का संकल्प : नेत्रदान को जन आंदोलन बनाइये

सुनील दत्त गोयल

कॉर्निया अंधता उन समस्याओं में है जिन्हें सही सिस्टम और समय पर कदमों से तेजी से कम किया जा सकता है–जरूरत है जागरूकता को कार्रवाई में बदलने की, अस्पताल–आधारित रिट्रीवल को बढ़ाने की, और यह सुनिश्चित करने की किदान हुआ हर कॉर्निया अधिकतम लोगों की रोशनी लौटाए। राजस्थान आई बैंक सोसाइटी (EBSR) की ताज़ा तिमाही रिपोर्ट दिखाती है कि पक्का इरादा, अच्छी काउंसलिंग और तेज़ प्रोसेसिंग मिलकर कैसे बड़ा असर लाते हैं।

क्यों जरूरी है भारत में दृष्टिदोष और अंधता का कुल बोझ घटा है, लेकिन कॉर्निया अंधता ऐसा क्षेत्र है जहां प्रत्यारोपण से सीधे रोशनी लौट सकती है–यानी समस्या के साथ समाधान भी मौजूद है। राष्ट्रीय अंधत्व एवं दृष्टिदोष सर्वे (2015–19) ने दिखाया कि देश में अंधता का कुल प्रचलन 0.36% तक घटा, पर कॉर्निया सहित रोके जा सकने वाले कारणों पर सतत फोकस 2025 तक 0.25% के लक्ष्य के लिए जरूरी है।

राजस्थान का उदाहरण जनवरी–जून 2025 में EBSR ने 1,518 कॉर्निया जुटाए और 930 प्रत्यारोपण करवाए; Q1 की उपयोगिता 56% से 2 में 67% तक पहुँची, और जून में 197% ट्रांसप्लांट तथा 82.77% उपयोगिता का मासिक रिकॉर्ड बना। स्थापना से जून 2025 तक EBSR ने 25,808 कॉर्निया प्राप्त कर 16,597 प्रत्यारोपण कराए हैं, और बताया है कि राज्य में उपयोग होने वाले कुल कॉर्निया का लगभग 96% वह सप्लाई करता है–यह पैमाने, गुणवत्ता आश्वासन और समुदाय–भागीदारी का मजबूत मॉडल है।

देश की तस्वीर: सरकारी डेटा क्या कहता है

भारत सरकार के ञ्झ्ँन्ह के अनुसार 2019 तक अंधता प्रचलन 0.36% पर आ चुका था और 2025 तक 0.25% का राष्ट्रीय लक्ष्य तय है–यानी प्रोग्रामेटिक सुधार सही दिशा दे रहे हैं।

लोकसभा में सरकार ने बताया कि औसतन 40–50% दान की गई आंखें/कॉर्निया सालाना प्रत्यारोपण में उपयोग हो पाती हैं; गुणवत्ता, उम्र और मेडिकल कारणों से सभी ऊतक ऑप्टिकल ग्रेड नहीं बन पाते–यही गैप HCRP और लैब–सक्षम प्रक्रिया से पाटा जा सकता है।

2024–25 तक NPCBVI के माध्यम से 1.17 करोड़ से अधिक लोग विभिन्न नेत्र सेवाओं से लाभान्वित हुए; इसमें कैटरेक्ट, चश्मे, और अन्य रोग–प्रबंधन के साथ केरेटोप्लास्टी भी शामिल है–यह इकोसिस्टम कॉर्निया के असर को गुणा देने वाली बैकबोन है।

नीति इतिहास बताता है किसरकार ने आई बैंकों/एडिसी को फंडिंग, स्टाफ ट्रेनिंग, और प्रतिजोड़ी कॉर्निया पर प्रतिपूर्ति जैसी सहूलियतें दीं; लक्ष्य 1 लाख वार्षिक ट्रांसप्लांट तक स्केल करना था–अस्पताल–आधारित रिट्रीवल से उपयोगिता 50–72% तक जाती दिखी है।

क्या सबसे ज्यादा असर करता है

अस्पताल से सीधी प्राप्ति (HCRP):ICU/इमरजेंसी/मॉर्चरी में प्रशिक्षित काउंसलर समय पर सहमतिऔर बेहतर ऊतक दिलाते हैं, जिससे उपयोगिता और ट्रांसप्लांट दोनों बढ़ते हैं। सरकारी स्वीकारोक्ति के मुताबिक उपयोगिता 40–50% के औसत से ऊपर ले जाने के लिए यही सबसे बड़ा लीवर है।

उपयोगिता–फर्स्टसोच: सर्जन नेटवर्क, समय पर लैब टेस्ट (सेरोलॉजी, स्पेक्युलर माइक्रोस्कोपी), और लेमलर तकनीकें (DSEK/DMEK/DALK) एक कॉर्निया से दो मरीजों तक को लाभ पहुँचा सकती हैं।

भरोसा और सम्मान: राजस्थान की जमीनी कहानियाँ–चलती एंबुलेंस में नेत्रदान, तीसरे दिन की बैठक में सार्वजनिक सम्मान–दिखाती हैं कि संवेदनशील संवाद और पारदर्शिता से परिवार समय पर हाँ कहते हैं।

नीतिऔर सिस्टम: तुरंत क्या करें HCRP को सार्वभौमिक बनाइए: सभी मेडिकल कॉलेजों और बड़े अस्पतालों में 24X7 काउंसलर व रिट्रीवल टीम, मॉर्चरी एक्सेस और फास्ट–ट्रैक लैब सपोर्ट अनिवार्य हों; राज्यों के डैशबोर्ड कलेक्शन नहीं, उपयोगिता और ऑपरेशन पर रैंक करें।

उपयोगिता पर फंडिंग: अनुदान/CSR प्रोत्साहन उन आई बैंकों को प्राथमिकता दें जो लगातार 60–70%+ उपयोगिता दिखाएँ और जिलों तक लेमलर ट्रेनिंग पहुँचाएँ।

रुकावटें हटाइए: मेडिकल–लीगल क्लियरेंस, ट्रांसपोर्ट और इंटर–स्टेट एक्सचेंज के मानक समय–सीमा के साथ तय हों; जिला–स्तर पर सेरोलॉजी और स्पेक्युलर की उपलब्धता डिस्कार्ड कम करती है।

डेटा पारदर्शिता: NPCBVI डैशबोर्ड पर तिमाही राज्यवार कलेक्शन, ट्रांसप्लांटेबल–ग्रेड यील्ड और वास्तविक ट्रांसप्लांट प्रकाशित होते रहें, ताकि कलेक्शन बनाम उपयोगिता का अंतर न रहे।

जन–भागीदारी: NSS/कॉलेज, धार्मिक व सामुदायिक नेतृत्व और शोक–समय संवाद की स्क्रिप्ट–जिन्हें राजस्थान अपना रहा है–को व्यापक बनाइए, ताकि फॉर्म से ज्यादा परिवार की तैयारी हो और हेल्पलाइन पर समय से कॉल पहुँचे।

राजस्थान से देश की सीख

Q2 की उछाल–एक महीने में 197 ट्रांसप्लांट और 82.77% उपयोगिता–यह साबित करती है कि जब अस्पताल रिट्रीवल, काउंसलिंग और लैब–लॉजिस्टिक्स एक सूत्र में आ जाते हैं, तो हर दान लगभग तय रोशनी में बदलता है। यही मॉडल राष्ट्रीय स्तर पर अपनाने से 40–50% की औसत उपयोगिता को 60–70%+ तक ले जाना संभव है।

तुरंत कदम

सरकारें: HCRP का सार्वभौमीकरण, उपयोगिता–आधारित स्कोरकार्ड, लेमलर ट्रेनिंग, और इंटर–स्टेट ऊतक–विनिमय के समयबद्ध मानक तय करें–2025 के 0.25% लक्ष्य की दिशा में यह तेज़ी जरूरी है।

अस्पताल: ICU/ER/मॉर्चरी में आई–डोनेशन चैंपियन नामित करें और ऑन–कॉल रिट्रीवल SOPs लागू करें–यही घंटों के भीतर सहमति को संभव बनाता है।

नागरिक: परिवार से अभी बात करें, टोल–फ्री नंबर सहेजें, और मौत के कुछ घंटों में सूचना दें–यही वो पल है जो संवेदना को दृष्टि में बदल देता है। हर कॉर्निया ऑपरेशन थिएटर तक पहुँचना चाहिए–और हर हाँ एक इलाज में बदलनी चाहिए। देश के पास नीति, कार्यक्रम और अनुभव का खाका मौजूद है; राजस्थान यह दिखा रहा है कि जमीन पर इसे कैसे जिया जाता है।

धन्यवाद,

–रोटेरियन सुनील दत्त गोयल,
महानिदेशक, इम्पीरियल चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री।

लेखक खुद भी अपने नेत्रदान का पंजीकरण करा चुके हैं। इसके अलावा अंगदान एवं देहदान का भी पंजीकरण कराया हुआ है।

विज़न डॉक्यूमेंट 2047 : रोजगार, आधारभूत संरचना, विकास से युवाओं को नए अवसरों तक

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश का विज़न डॉक्यूमेंट 2047, केवल एक भविष्य की कल्पना नहीं, बल्कि युवाओं के लिए बनाए जा रहे ठोस अवसरों का रोडमैप है

आकांक्षा पालावत

दुनिया आज एआई, पर्यावरण, क्लीन एनर्जी, स्पेस एक्सप्लोरेशन जैसे क्षेत्रों में जबर्दस्त बदलाव के दौर से गुजर रही है। यह चुनौती भी है और अवसर भी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस चुनौती को अवसर में बदलने का संकल्प लेते हुए राज्य के साढ़े आठ करोड़ लोगों की भागीदारी से वर्ष 2047 तक राजस्थान को पूर्ण विकसित बनाने के लिए विजन डाक्यूमेंट 2047 जारी किया है और इस पर मिशन मोड पर कार्य शुरू कर दिया है। राज्य को देश का ग्रोथ इंजन बनाने के इस विजन डॉक्यूमेंट की हर नीति, हर योजना और हर प्रयास का केंद्र युवा हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश का विज़न डॉक्यूमेंट 2047, केवल एक भविष्य की कल्पना नहीं बल्कि आज के और आने वाले कल के युवाओं के लिए बनाए जा रहे ठोस अवसरों का रोडमैप है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सोच साफ है कि जब तक युवा आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक राज्य प्रगति नहीं कर सकता क्योंकि युवा सम्भावना, एनर्जी और इनोवेशन का केन्द्र है इसलिए शिक्षा, उद्यिमता, रोजगार, स्वास्थ्य और स्किल डेवलपमेंट को प्राथमिकता दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से राजस्थान ने विकसित राज्य बनने का लक्ष्य तय किया है। वर्ष 2030 तक 350 बिलियन डॉलर और 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का सपना, उन युवाओं की आकांक्षाओं को समर्पित है जो आज मेहनत कर रहे हैं, सीख रहे हैं, कुछ नया करना चाहते हैं। इस विज़न में हर युवा को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी, आधुनिक स्किल्स के साथ रोजगार की तैयारी होगी, हर क्षेत्र में इनोवेशन और स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा और सबसे अहम युवाओं को प्रदेश की विकास यात्रा का भागीदार बनाया जाएगा।

आज का युवा सिर्फ नौकरी नहीं, अपनी पहचान चाहता है। इसी सोच के साथ विश्वकर्मा युवा उद्यमी योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत 18 से 45 वर्ष के युवाओं को 2 करोड़ रुपये तक का ऋण मिलेगा जिससे वे अपना खुद का स्टार्टअप या बिज़नेस शुरू कर सके। महिलाओं, एससी, एसटी दिव्यांग और ग्रामीण युवाओं को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। ट्रेनिंग, मार्गदर्शन और मार्केट से जोड़ने जैसी सुविधाएँ भी उपलब्ध होगी। यह योजना युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ–साथ एक नया आत्मविश्वास भी दे रही है।

जयपुर में बन रहा राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़ न केवल एक सुपर–स्पेशियलिटी संस्थान होगा बल्कि मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च के क्षेत्र में युवाओं के लिए नए अवसर खोलेगा। डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनेगा। रिसर्च, ट्रेनिंग और इंटर्नशिप के जरिए मेडिकल छात्र राजस्थान में ही ग्लोबल स्तर की शिक्षा और अनुभव प्राप्त कर सकेंगे। स्वास्थ्य क्षेत्र में रोज़गार और प्रोफेशनल ग्रोथ के नए रास्ते खुलेंगे।

राइजिंग राजस्थान समिट–2024 में 35 लाख करोड़ रूपये के एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। इनमें से 4 लाख करोड़ रूपये के एमओयू पर काफी प्रगति हासिल की जा चुकी है। दिसम्बर, 2025 में जयपुर में समिट का आयोजन कर इन सभी एमओयू की प्रगति पर मंथन कर विकास की नई राह पर राज्य को अग्रसर किया जाएगा। राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी, रीको डायरेक्ट अलोटमेंट पॉलिसी, डेटा सेंटर पॉलिसी, मिनरल पॉलिसी, टेक्सटाइल एंड अपेरल पॉलिसी से राज्य में औद्योगिक विकास को नया स्वरूप मिला है। न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण, कम निवेश में अधिकतम रोजगार और विश्वमंच पर भारत को सॉफ्ट पावर व सांस्कृतिक नेतृत्व का केन्द्र बनाने के लिए महत्वपूर्ण पर्यटन सेक्टर के लिए भी इस विजन डॉक्यूमेंट में बहुत कुछ है।

जोधपुर–पाली इन्डस्ट्रियल कॉरिडोर के पार्ट दिल्ली– मुम्बई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में 19 हजार करोड़ रूपये के निवेश से पश्चिमी राजस्थान में आधारभूत ढांचे, रोजगार और निवेश को नया आयाम मिलेगा। इससे 50 हजार प्रत्यक्ष और 2 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। राजस्थान इन्टीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी–2024 के माध्यम से वर्ष 2030 तक 125 गीगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य है। वर्ष 2027 तक सभी किसानों को दिन में विद्युत सप्लाई का लक्ष्य पूर्ण होने से अन्नदाता को राहत और सुविधा मिलेगी। राज्य सरकार का लक्ष्य पब्लिक सेक्टर में 4 लाख और प्राइवेट सेक्टर में 6 लाख नए रोजगार देना है। राज्य सरकार ने नई भूमि आवंटन नीति–2025 लागू की है जिससे शिक्षा, हेल्थ और इंडस्ट्री से जुड़े युवाओं को ज़मीन, निवेश और विकास के लिए मदद मिलेगी। वहीं, एयरो स्पोर्ट्स भूमि लीज नीति रोमांचक खेलों, टूरिज्म और इवेंट्स से जुड़े युवाओं के लिए करियर के नए दरवाज़े खोल रही है। चाहे आप एजुकेशन सेक्टर में हो, हेल्थकेयर, टूरिज्म या एडवेंचर में सरकार हर दिशा में युवाओं को केंद्र में रखकर फैसले ले रही है। केन्द्र सरकार की खेलो इंडिया पॉलिसी–2025 भी इस दिशा में मददगार साबित होगी। राजस्थान में युवाओं के लिए आज जो किया जा रहा है, वही उन्हें आने वाले वर्षों में एक ग्लोबल सिटीजन बनाएगा। विश्वकर्मा योजना, रिम्स, राजस्थान मंडपम, सोलर और ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स, स्किल मिशन– ये सब मिलकर एक ऐसा इकोसिस्टम बना रहे हैं जहाँ हर युवा को अवसर मिलेगा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का यह विज़न साफ है कि युवा केवल लक्षित समूह नहीं, विकास के भागीदार हैं। राजस्थान अब ऐसा प्रदेश बन रहा है जहाँ सपने सिर्फ देखे नहीं जाते, उन्हें साकार करने की व्यवस्था भी सरकार कर रही है। यह समय है पारम्परिक सोच से आगे बढ़ने का, सीखने, करने और बढ़ने का क्योंकि जब युवा आगे बढ़ेगा, तब ही राजस्थान 2047 का सपना हकीकत बनेगा। यह डॉक्यूमेंट नहीं हमारा भविष्य है, राजस्थान और इसके युवाओं का भविष्य।

आकांक्षा पालावत,
सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर।

बचत मेले में युवाओं और बच्चों को बचत करने की सीख दी

डीडवाना, (निसं)। भारतीय डाक विभाग की ओर से नागौर डाक मंडल के तत्वावधान में डीडवाना में जिला स्तरीय विशाल बचत मेले का आयोजन किया गया। इस मेले का उद्देश्य आमजन, विशेषकर युवाओं और बच्चों को बचत के महत्व से जोड़ना और भविष्य के लिए सुरक्षित निवेश की दिशा में प्रेरित करना रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर और रामावतार सोनी डाक अधीक्षक द्वारा किया, जहां डाक विभाग के अधिकारी–कर्मचारी, विद्यार्थी और बड़ी संख्या में अभिभावक मौजूद रहे।

अधीक्षक डाकघर नागौर मंडल रामावतार सोनी ने बताया कि शिविर के दौरान 11 हजार नए बचत खाते खोलने का लक्ष्य रखा गया है और लोगों की उत्साहपूर्ण भागीदारी से लगातार खाते खोले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मेलों का मकसद आमजन को वित्तीय साक्षर बनाना और बचत की आदत विकसित करना है। डाक निरीक्षक राज चौधरी ने जानकारी दी कि मेले में स्कूली बच्चों के लिए क्विज, निबंध, पत्र लेखन और पेंटिंग प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं। पत्र लेखन का विषय बचत का महत्व और डाकघर बचत योजनाएँ और हमारा भविष्य रखा गया, जबकि पेंटिंग प्रतियोगिता का विषय बचत से सुनहरा भविष्य था। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में बच्चों ने बचत योजनाओं और वित्तीय साक्षरता पर ज्ञान का प्रदर्शन किया।

कन्या महाविद्यालय में खेल प्रतियोगितायें शुरु

भीलवाड़ा, (निसं)। सेठ मुरलीधर मानसिंहका राजकीय कन्या महाविद्यालय में शुक्रवार को राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष में खेल विभाग, महिला प्रकोष्ठ एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वावधान में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की स्मृति में श्रद्धांजलि कार्यक्रम एवं तीन दिवसीय खेल गतिविधियों का आगाज प्राचार्य प्रोफेसर सावन कुमार जांगिड़ की अध्यक्षता में किया गया। इस अवसर पर प्रोफेसर जांगिड़ ने मेजर ध्यानचंद के जीवन पर प्रकाश डाला तथा छात्राओं को खेलों का महत्व समझाते हुए उन्हें खेल संबंधी सभी गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। खेल प्रभारी सुधा नवल ने तीन दिवसीय खेल गतिविधियों की रूपरेखा प्रस्तुत की। शुक्रवार प्रथम दिवस पर योग एवं प्राणायाम सत्र का आयोजन किया गया। सेठ मुरलीधर मानसिंहका राजकीय कन्यामहाविद्यालय के सहायक आचार्य प्रणव कुमार व्यास ने संकाय सदस्यों एवं छात्राओं को योग के महत्व के बारे में विशेष जानकारी प्रदान करते हुए योगाभ्यास एवं प्राणायाम करवाया। इस अवसर पर छात्राओं के लिए 'खेल एवं स्वास्थ्य' विषयक निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन नेहा शर्मा एवं हेमंता मीणा द्वारा किया गया, जिसमें छात्राओं ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन सहायक आचार्य दिलीप कुमार शर्मा ने किया।

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

शनिवार 30 अगस्त, 2025

भाद्रपद मास, शुक्ल पक्ष, सप्तमी तिथि, शनिवार, विक्रम संवत 2082, विशाखा नक्षत्र दिन 2:37 तक, ऐन्द्रयन योग दिन 3:10 तक, गर करण प्रातः 9:34 तक, चन्द्रमा प्रातः 7:53 से वृश्चिक राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य–सिंह, चन्द्रमा–वृश्चिक, मंगल–कन्या, बुध–कर्क, गुरू–मिथुन, शुक्र–कर्क, शनि–मीन, राहु–कुम्भ, केतु–सिंह राशि में।

आज त्रिपुष्कर योग सूर्योदय से दिन 2:37 तक है। भद्रा रात्रि 10:47 से आरम्भ होगी। आज बुध मघा सिंह राशि में प्रवेश करेगा। आज मुक्ताभरण सप्तमी, सन्तान और टुकड़ी सप्तमी, ललिता सप्तमी है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: शुभ 7:44 से 9:18 तक, चर 12:28 से 2:02 तक, लाभ–अमृत 2:02 से 5:11 तक।

राहूकाल: 9:00 से 10:30 तक। सूर्योदय 6:09, सूर्यास्त 6:46

मेष

अपनी कार्य योजना को सीमित रखें। चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। नवीन कार्यों में परेशानी हो सकती है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। यात्रा टालना ठीक रहेगा।

वृष

परिवार में प्रसन्नता–हर्षोल्लास का माहौल रहेगा। परिवार में धार्मिक–मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। सामूहिक प्रयासों से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है।

मिथुन

स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। अस्त–व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। विवादित मामलों से राहत मिलेगी। आर्थिक मामलों में संतुलन बना रहेगा। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी।

कर्क

परिवार में शुभ–मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में सुख–सुविधाएं बढ़ेगी। समय रचनात्मक कार्यों में व्यतीत होगा। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।

सिंह

घर–परिवार के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। अतिथियों के आगमन से दिनचर्या अस्त–व्यस्त हो सकती है।

कन्या

परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। मित्रों/रिश्तेदारों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

तुला

व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है। अटके हुए व्यावसायिक कार्य बनने लगेंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृश्चिक

व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक परेशानियां दूर होने लगेगी। नौकरीपेशा व्यक्तियों का प्रभाव–प्रभुत्व बढ़ेगा।

धनु

आज समय अनर्गल कार्यों में खराब हो सकता है। मन में असंतोष बना रहेगा। घर–गृहस्थी के खर्चों में वृद्धि होगी। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी।

मकर

आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। मन में असंतोष बना रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

कुंभ

व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मीन

नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। परिवार में शुभ–मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।